

गणेशमल जशराज

बनाम

गुजरात सरकार और अन्य

30 अक्टूबर, 1979

[पी.एन. भगवती और वी.डी. तुलजापुरकर, जे.जे.]

सजा - खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 के तहत संविधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम सजा - अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 229 के तहत अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जांच के बाद अभिवाक चर्चा के परिणामस्वरूप उसने लिखित रूप से ऐसा किया है - मजिस्ट्रेट केवल दोष के अभिवाक से संतुष्ट नहीं, परन्तु सांविधिक न्यूनतम सजा से कम सजा दी - क्या सजा दूषित है - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 229, 235 सपठित पीओएफए 1954 की धारा 16

अपीलकर्ता पर राज्य के खाद्य निरीक्षक, प्रतिवादी नंबर 2 को मिलावटी हल्दी पाउडर बेचने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (ए) (1) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। भले ही अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए अपराध के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और विचारण का फैसला किया, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच के बाद, "अभिवाक चर्चा" के परिणामस्वरूप, उसने उसके प्रति इस तथ्य के कारण कि वह एक गरीब आदमी था और उसका अपराध पहला था, अपना अपराध स्वीकार करते हुए और नरमी की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को धारा 16 (ए) (1) पीओएफए, 1954 के तहत अपराध का दोषी ठहराते

हुए न्यायालय के उठने तक साधारण कारावास और 300/- रुपये का जुर्माना या अन्यथा एक महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय को एक गुमनाम आवेदन के माध्यम से पता चला कि अपीलकर्ता को अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकता के उल्लंघन में एक दिन के साधारण कारावास के साथ हल्के से छोड़ दिया गया था, अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का स्वतः संज्ञान लेते हुए अपीलकर्ता को वृद्धि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। सजा सुनाई गई और सुनवाई के बाद अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन सजा को तीन महीने के साधारण कारावास तक बढ़ा दिया और जुर्माना भी बढ़ाकर 500/- कर दिया।

विशेष अनुमति द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

जब अभियुक्त द्वारा "अभिवाक-चर्चा" या अन्यथा के परिणामस्वरूप अपना अपराध स्वीकार कर लिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन थोड़ा सतही और लापरवाहीपूर्ण हो जाने की संभावना है और न्यायालय, मामले को संदर्भित करने के लिए तैयार हो सकता है। साक्ष्य को आलोचनात्मक रूप से उसकी विश्वसनीयता का आकलन करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि यांत्रिक रूप से अपराध स्वीकार करने के समर्थन में औपचारिकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लिया जाता है, तो साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण भिन्न होने की संभावना होगी। [1117 बी-डी]

मौजूदा मामले में, यह सच है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपनी सजा का आदेश केवल अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की स्वीकृति पर आधारित नहीं किया था, लेकिन उनके फैसले से यह स्पष्ट है कि उनका निष्कर्ष अपीलकर्ता की ओर से अपराध

स्वीकार करने से अप्रभावित नहीं था और इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखना सही नहीं होगा। [1117 बी-सी]

[इसलिए, न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच के चरण से आगे की कार्रवाई के लिए मामले को विचारण न्यायालय में भेज दिया। न्यायालय ने पीओएफए के तहत मामलों को दर्ज करने और अधिकारियों द्वारा (सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए) जांच करने के तरीके की भी निंदा की और कुछ दिशानिर्देशों का संकेत दिया। ताकि खाद्य अपमिश्रण निवारण कानून का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके और कल्याणकारी कानूनों के संबंध में अपेक्षा और पूर्ति के बीच के बड़े अंतर को पाट दिया जाए।]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं.632/1979

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 499/78 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30-1-1979 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

के.एन.भट्ट, अपीलार्थी की ओर से।

एम. एन. श्रॉफ, प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का आदेश दिया गया -

**भगवती, न्यायाधिपति.**

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, झगड़िया द्वारा अपीलकर्ता पर खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16(1)(ए) (i) के तहत अपराध के लिए लगाई गई सजा को बढ़ा दिया गया है।

अपीलकर्ता पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(i) के तहत प्रतिवादी नंबर 2, जो उस समय राज्य के रोजगार में खादध निरीक्षक था, को मिलावटी हल्दी पाउडर बेचने का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ लगाए गए अपराध के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और उसके बाद विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी नंबर 2 और एक ठाकुर भाई के साक्ष्य का नेतृत्व किया, जो पंच गवाहों में से एक थे, जिनकी उपस्थिति में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा हल्दी पाउडर खरीदा गया था और प्रमाण के रूप में सार्वजनिक विश्लेषक का प्रमाण पत्र भी दिखाया गया था कि हल्दी पाउडर मिलावटी था। अभियोजन ने अपना मामला बंद कर दिया और उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलकर्ता की जांच की गई। उसी दिन, संभवतः अभिवाक-चर्चा के परिणामस्वरूप, जिसमें विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शायद एक पक्ष था, अपीलकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि चूंकि वह एक गरीब आदमी था और यह उसका पहला अपराध था, इसलिए नरमी बरती जाए। इसके बाद विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(i) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए न्यायालय के उठने तक साधारण कारावास भुगतने और 300/- रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया या व्यतिक्रम में एक माह के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि एक गुमनाम आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय को पता चला कि यद्यपि अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(i) के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम सजा निर्धारित थी, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की अनिवार्य आवश्यकता के उल्लंघन में अपीलकर्ता को केवल एक दिन के साधारण कारावास के साथ हल्के से छोड़

दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का स्वतः संज्ञान लेते हुए अपीलकर्ता को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि क्यों नहीं उस पर लगाई गई सजा को बढ़ाया जाना चाहिए और इस प्रकार शुरू की गई कार्यवाही को आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन के रूप में माना गया। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन सुनवाई के लिए आया था, ने यह विचार किया कि यद्यपि अपीलकर्ता ने अभियोजन साक्ष्य के समापन के बाद एक आवेदन दायर करके अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के अपने आदेश में अपराध की स्वीकृति को आधार नहीं बनाया था। लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सबूतों पर विचार किया था और ऐसे सबूतों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अपीलकर्ता उसके खिलाफ लगाए गए अपराध का दोषी था और इसलिए, दोषसिद्धि दूषित नहीं हुई थी, लेकिन जहां तक सजा का सवाल है, यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 16(1)(ए)(i) की आवश्यकता का उल्लंघन था, जिसमें न्यूनतम तीन महीने के कारावास की सजा का प्रावधान है और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने सजा को तीन महीने के साधारण कारावास तक बढ़ा दिया और जुर्माने की राशि भी 300/- रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये कर दी। इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील में उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर आपत्ति जताई गई है।

अपीलकर्ता की ओर से मुख्य तर्क यह था हालाँकि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए सबूतों पर विचार किया और केवल अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की स्वीकृति पर कार्रवाई नहीं की, साक्ष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अपराध स्वीकार करने से प्रभावित था और चूँकि अभियोजन साक्ष्य शुरू होने से पहले अपनी दलील देने के चरण में अपीलकर्ता द्वारा अपराध की स्वीकृति नहीं की गई थी, लेकिन केवल अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद और दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 313 के तहत उससे पहले ही पूछताछ की जा चुकी थी, दोषसिद्धि दूषित हो गई थी। अब, यह सच है कि जब अपीलकर्ता को अभियोजन साक्ष्य शुरू होने से पहले अपनी दलील देने के लिए बुलाया गया, तो उसने अपने खिलाफ लगाए गए अपराध के संबंध में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसकी जांच पूरी होने के बाद ही उसने संभवतः दलील सौदेबाजी के परिणामस्वरूप अपराध स्वीकार किया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट उन परिस्थितियों में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के संबंध में अपने निर्णय तक पहुँचने में अपीलकर्ता द्वारा की गई अपराध की स्वीकृति को ध्यान में रखने का हकदार नहीं था। यह सच है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषसिद्धि के अपने आदेश को केवल अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की स्वीकृति पर आधारित नहीं किया, लेकिन उनके फैसले से यह स्पष्ट है कि उनका निष्कर्ष अपीलकर्ता की ओर से अपराध की स्वीकृति से अप्रभावित नहीं था। अपीलकर्ता इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब अभिवाक चर्चा के परिणामस्वरूप या अन्यथा अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन थोड़ा सतही हो जाने की संभावना है और असावधान और न्यायालय को साक्ष्य की विश्वसनीयता का आकलन करने की दृष्टि से गंभीर रूप से नहीं, बल्कि अपराध स्वीकार करने के समर्थन में औपचारिकता के तौर पर यंत्रवत् संदर्भित करने का आदेश दिया जा सकता है। जब अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लिया जाता है, तो साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण भिन्न होने की संभावना होगी। यहां यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का दृष्टिकोण अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की स्वीकृति से प्रभावित था और इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखना सही नहीं होगा।

हम तदनुसार अपील स्वीकार करते हैं, अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को बढ़ाने के उच्च न्यायालय के आदेश और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त करते हैं और मामले को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रतिप्रेषित करते हैं ताकि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण के चरण से आगे बढ़ सके और अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य के आधार पर और यदि अपीलकर्ता बचाव में कोई साक्ष्य देने का विकल्प चुनता है, तो ऐसे अतिरिक्त साक्ष्यों को भी ध्यान में रखने के बाद और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की स्वीकृति से किसी भी तरह से प्रभावित या प्रभावित हुए बिना मामले का निस्तारण कर सके ।

इससे पहले कि हम इस मामले को छोड़ें, हमें अफसोस के साथ यह देखना चाहिए और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस पर कोई विवाद नहीं किया, कि न्यायालयों में आने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट के ज्यादातर मामले किराना विक्रेताओं दूध-विक्रेता आदि जैसे छोटे व्यापारियों के खिलाफ निर्देशित होते हैं। यह सामान्य ज्ञान है कि ये छोटे व्यापारी अपने द्वारा बेची जाने वाली खाद्य सामग्री थोक विक्रेताओं से खरीदते हैं और कभी-कभी सीधे निर्माताओं से भी खरीदते हैं और अक्सर मिलावट या तो थोक विक्रेताओं द्वारा या निर्माताओं द्वारा की जाती है। आमतौर पर यह छोटे खुदरा विक्रेता नहीं हैं जो अपने द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। फिर भी केवल छोटे खुदरा विक्रेता ही खाद्य निरीक्षकों की पकड़ में आते हैं और खाद्य विभाग की जांच मशीनरी कुछ अजीब और अस्पष्ट कारणों से थोक विक्रेताओं और निर्माताओं पर अपना ध्यान नहीं देती है। छोटे-मोटे व्यापारी, जो मुश्किल में अपना गुजारा करते हैं, उन्हें खाद्य सामग्री बेचने के लिए जेल भेज दिया जाता है, जो अक्सर इतनी मात्रा में होती है कि वे मिलावट नहीं करते। और थोक विक्रेता और निर्माता जो वास्तव में खाद्य सामग्री में मिलावट करते हैं और दूसरों के

दुख पर अपना पेट भरते हैं, कानून की पकड़ से बच जाते हैं। खाद्य निरीक्षण विभाग छोटे व्यापारियों को पकड़कर और अपनी घोर उदासीनता एवं निष्क्रियता से अपने आँकड़ों पर इतराता है। थोक विक्रेताओं और निर्माताओं को दंडात्मक कानून से अछूते और अप्रभावित रहते हुए अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देता है। नतीजा यह हो रहा है कि जनता के मन में यह गलत धारणा बन रही है कि कानून का पालन ठीक से हो रहा है। जबकि वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि केवल छोटे व्यापारी ही, जो अक्सर मिलावट के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं होते हैं, पकड़े जाते हैं और जेल भेज दिए जाते हैं, जबकि वास्तविक मिलावटखोरों के खिलाफ कानून का कोई प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होता है। यह एक विफलता है जिसे हम अपने कई कानूनों के कार्यान्वयन में देखते हैं। केवल छोटी मक्खियाँ ही इन कानूनों के जाल में फँसती हैं जबकि बड़ी मक्खियाँ बच जाती हैं। बड़े आर्थिक अपराधियों के प्रति नरम न्याय और विनम्र अपराधियों के प्रति कठोर न्याय का यह सिंड्रोम एक प्रणालीगत कमजोरी है जो कानून के शासन की विश्वसनीयता को ही प्रभावित करती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक गुमनाम कवि ने इस प्रणालीगत कमी के सामाजिक आयाम को सामने रखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा:

कानून पुरुष और महिला दोनों को बंद करता है

जो आम से हंस चुराता है,

लेकिन बड़े अपराधी को खुला छोड़ दो,

जो हंस से आम चोरी करता है।

हम यह समझने में असफल रहते हैं कि छोटे खुदरा विक्रेता से नमूने लेते समय खाद्य निरीक्षक यह पता लगाने की परवाह क्यों नहीं करते कि उसने किस थोक विक्रेता या निर्माता से विशेष खाद्य सामग्री खरीदी है और ऐसे थोक विक्रेता या निर्माता का



नाम पता करने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हैं। ऐसे थोक विक्रेता या निर्माता के व्यवसाय के स्थान पर जाएं और यह पता लगाने के लिए नमूने लें कि उसके द्वारा बेची जा रही खाद्य सामग्री मिलावटी है या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य निरीक्षकों की चिंता केवल छोटे व्यापारियों को पकड़ने की है, न कि बड़े थोक विक्रेताओं या निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की, जो अक्सर असली दोषी होते हैं। अन्यथा, हमें समझ नहीं आता कि थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के खिलाफ न्यायालयों में इतने कम मामले क्यों लाए जाते हैं। कानून के कार्यान्वयन से यह धारणा बनती है कि यह एक ऐसा कानून है जो केवल छोटे लोगों के खिलाफ लागू होता है और अमीर और संपन्न लोग इसकी पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा कानून छोटे व्यापारियों के खिलाफ बहुत कठोरता से काम करता है क्योंकि न्यूनतम सजा का प्रावधान है और छोटे व्यापारियों को खाद्य सामग्री बेचने के लिए तीन या छह महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है, जिसमें उन्होंने स्वयं मिलावट नहीं की हो लेकिन दूसरों द्वारा मिलावट की गई हो। विशेषकर तब जब उनके पास खरीदारी के समय यह सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है कि खाद्य सामग्री मिलावटी है या नहीं। यह निःसंदेह सत्य है कि अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि डीलर द्वारा उस थोक विक्रेता या निर्माता से, जिससे उसने खाद्य सामग्री खरीदी है, लिखित में वारंटी ले ली है, तो उसे आपराधिक दायित्व से छूट मिल जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि हमारे जैसे गरीब देश में जहां छोटे व्यापारी छोटी-छोटी दैनिक बिक्री से अपना गुजारा कर रहे हैं और उनमें से कई कानून के प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं और इसके अलावा थोक विक्रेताओं और निर्माताओं की दया पर निर्भर हैं। यह प्रावधान छोटे व्यापारियों को कोई वास्तविक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां उन्हें थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के पापों के लिए जेल जाना पड़ सकता है, जिससे उनके परिवार पर अनकही कठिनाई आ सकती है। इसलिए, हम खाद्य निरीक्षण विभाग से पुरजोर आग्रह करेंगे कि वह छोटे व्यापारियों को पकड़कर मिलावट विरोधी कानून को तिलांजलि देकर संतुष्ट न रहे, बल्कि अपनी जांच मशीनरी

का पूरा गुस्सा थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के खिलाफ निर्देशित करें, जो अधिकांश मामलों में मिलावटखोर हैं। छोटे खुदरा विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली खाद्य सामग्री में मिलावट के लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं। तभी खाद्य अपमिश्रण निवारण कानून का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा और कल्याणकारी कानून के संबंध में अपेक्षा और पूर्ति के बीच का बड़ा अंतर पाटा जा सकेगा।

वी.डी.के.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

**अस्वीकरण-** इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

\*\*\*\*\*